भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3192

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

बिहार में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

3192. श्री मनोज कुमारः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सासाराम लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कैमूर भभुआ और रोहतास जिलों सहित बिहार राज्य में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के लिए सामान्य और एससीएसपी/टीएसपी बजट के अंतर्गत कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है और उसका उपयोग कितना हुआ है;
(ग) सासाराम और कैमूर भभुआ में आईटी पार्क की स्थिति क्या है;
(घ) बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों सहित अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उन छात्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कम्प्यूटर शिक्षा और कौशल प्राप्त है और उन्हें एनआईईएलआईटी के अल्पकालिक, दीर्घकालिक प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से नौकरी दी गई है।
(ङ) क्या सरकार की सासाराम लोक सभा के कैमूर और रोहतास जिलों में नए नाइलिट केन्द्र सहित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना स्थापित करने की योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):** प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने जुलाई, 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करें।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने नागरिक-केंद्रित सेवाओं के ऑनलाइन वितरण को सक्षम करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास और कार्यान्वयन, लाभार्थी की पहचान के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से सेवा वितरण का विस्तार शामिल है। कुछ प्रमुख पहलों का विवरण इस प्रकार है:

- **डिजिलॉकर:** डिजिलॉकर ने आम नागरिक के लिए मूल जारीकर्ता से प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक किसी भी समय पहुंच प्रदान की है। डिजीलॉकर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **67.17+ करोड़ से** अधिक उपयोगकर्ता इसके साथ पंजीकृत हैं और प्लेटफॉर्म पर 2456 जारीकर्ताओं से 967.01+ करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। डिजिलॉकर सेवाओं

का लाभ उठाने के लिए बिहार राज्य में **255.78 लाख** से अधिक आधार सक्षम पंजीकरण हुए हैं।

- **यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग),** सभी सरकारी सेवाओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन, चालू है और व्यक्तियों के लिए **2446+ सेवाएं** प्रदान करता है। बिहार राज्य में, उमंग प्लेटफॉर्म पर एकीकृत/ऑनबोर्ड की गई विभिन्न विभागों की सेवाओं में ई-लाभार्थी (4 सेवाएं), मेरा राशन (1 सेवा), और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-बिहार (2 सेवाएं) शामिल हैं।

- **ई-साइन:** यह आधार धारक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर प्रदान करता है। बिहार राज्य में अब तक 37.72 करोड़ ई-साइन जारी किए गए हैं और 610.78 लाख ई-साइन जारी किए गए हैं।

- **आधार:** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय-आधारित विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है। अब तक **143.80+ करोड़ आधार आईडी** तैयार की जा चुकी हैं। बिहार राज्य में 12.27 करोड़ आधार आईडी बनाई गई हैं।

- **सामान्य सेवा केंद्र** – सीएससी ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जनवरी, 2026 तक, देश भर में (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) 5.54 लाख सीएससी कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 4.32 लाख सीएससी ग्राम पंचायत स्तर (ग्रामीण) पर कार्य कर रहे हैं। बिहार राज्य में कुल **62,106 सीएससी कार्य** कर रहे हैं, जिनमें कैमूर भभुआ में 905 सीएससी और रोहतास जिले में 1376 सीएससी शामिल हैं। सीएससी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिलावार ब्यौरा https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है और सेवाओं की सूची https://csc.gov.in/ पर उपलब्ध है।

- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन):** एनकेएन राष्ट्रीय/राज्य डेटा केंद्रों (एनडीसी/एसडीसी), राज्य-व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) के डिजिटल-ट्रैफिक को वहन करता है और विभिन्न डिजिटल इंडिया पहलों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करता है, और विभिन्न जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं, जिला कनेक्टिविटी आदि के डिजिटल-ट्रैफिक को वहन करता है। यह संसाधन साझाकरण और सहयोगात्मक अनुसंधान की सुविधा के लिए देश भर में उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को भी आपस में जोड़ता है, जिससे राष्ट्रीय सरकार नेटवर्क (एनजीएन) और अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क (आरईएन) दोनों का समर्थन होता है। एनकेएन के तहत कुल 1,823 संस्थान जुड़े हुए हैं, जिनमें बिहार के 54 संस्थान शामिल हैं, जबकि पूरे भारत में 560 जिलों को कवर करने वाले 681 जिला लिंक चालू हैं, जिनमें से 43 बिहार में हैं।

- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी):** यह मंच योजना के स्वामित्व वाले मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से आवेदनों को संसाधित करने और छात्रवृत्ति/धन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) 7.47 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सेवा प्रदान करता है, जिसका कुल वितरण 44,181+ करोड़ रुपये से अधिक है। अब तक, 13 मंत्रालयों/विभागों और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 153 स्कीमों को एनएसपी में शामिल किया गया है। 31 जनवरी 2026 तक, सासाराम लोकसभा क्षेत्र के कैमूर भभुआ और रोहतास जिलों सहित बिहार राज्य में 1,460 करोड़ रुपये की लगभग 29 लाख छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं।

- **माईगव**: माईगव भारत सरकार का एक नागरिक जुड़ाव मंच है जो नीति निर्माण में लोगों को शामिल करने के लिए कई सरकारी निकायों/मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और सार्वजनिक हित और कल्याण के मुद्दों/विषयों पर लोगों की राय मांगता है। वर्तमान में, **6.11+ करोड़ से** अधिक नागरिक माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो माईगव प्लेटफॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों सहित युवाओं को स्किलिंग/अपस्किलिंग प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। इन पहलों का उद्देश्य बिहार राज्य सहित देश भर में उभरते और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार जनशक्ति विकसित करना है। प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

(i). पीएमजीदिशा: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया गया था। यह योजना 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई। योजना के प्रमुख पहलू थे:

- यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल साक्षरता पहलों में से एक थी
- देश भर में 6.39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया (6 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष)
- बिहार राज्य में 74,12,740 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था, जिसमें कैमूर (भभुआ) के 1,28,125 और रोहतास जिले के 2,21,634 उम्मीदवार शामिल थे।

(ii). फ्यूचरस्किल्स प्राइम: फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम एमईआईटीवाई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) की एक सहयोगी पहल है जिसका उद्देश्य भारत को एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रतिभा राष्ट्र बनाना है। प्रमुख विशेषताएं हैं:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, आईओटीएस, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, एआर/वीआर आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग
- वास्तविक रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग के परामर्श से पाठ्यक्रम विकसित किए जाते हैं।
- पोर्टल को उनकी योग्यता और आकांक्षाओं के अनुरूप कौशल प्रमाण पत्र अर्जित करने के लिए https://futureskillsprime.in/ पर ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।
- कार्यक्रम के तहत, अब तक 17.24+ लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन/प्रशिक्षण लिया है।
- बिहार राज्य में, कुल 26,000 उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित / प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें रोहतास जिले के 800 से अधिक और कैमूर भभुआ जिले के 300+ से अधिक शामिल हैं।

(iii). राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट):

- नाइलिट डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम जैसे कंप्यूटर अवधारणा में जागरूकता (एसीसी), कंप्यूटर अवधारणाओं पर पाठ्यक्रम (सीसीसी) आदि प्रदान करता है।
- नाइलिट ने डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा जागरूकता सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत 43 लाख+ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

- प्रशिक्षण 56 नाइलिट केंद्रों और 9000+ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों/सुविधा केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- नाइलिट राज्य में कौशल विकास गतिविधियों की समग्र निगरानी के लिए पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर में स्थित अपने 3 केंद्रों के माध्यम से बिहार के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान कर रहा है। अपने केंद्रों के अलावा, नाइलिट के पास राज्य भर में फैले 300 से अधिक सुविधा केंद्र हैं, जिनमें से 06 केंद्र डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों (डीएलसी) को बढ़ावा देने के लिए रोहतास और कैमूर जिलों में स्थित हैं।
- पिछले 2 वर्षों में, बिहार राज्य में विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पावधि में कुशल उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	2023-2024	2024-2025
अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	1,186	985
अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	137	96

(iv) इसके अलावा, **नाईलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म** उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत नाइलिट द्वारा शुरू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य फ्रंटियर डोमेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार, उद्योग-संरेखित कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, उद्योग 4.0 और अन्य उभरते डोमेन में वास्तविक समय के प्रयोग के लिए अंतर्निहित वर्चुअल लैब भी हैं। एनडीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रत्येक शिक्षार्थी एनएसक्यूएफ-संरेखित पाठ्यक्रमों तक कभी भी-कहीं भी पहुंच प्राप्त कर सकता है। अब तक 55,000 से अधिक उम्मीदवारों ने एनडीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराया है।

भारत सरकार छोटे शहरों और कस्बों सहित पूरे भारत में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में, टियर-2 और टियर-3 शहरों में 60 केंद्रों के साथ पूरे भारत के 68 शहरों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए गए हैं। एसटीपीआई केंद्र इनक्यूबेशन सेवाएं, हाई स्पीड डेटा संचार सेवाएं, क्लाउड सेवाएं और अन्य वैधानिक सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में, बिहार में पटना, भागलपुर और दरभंगा में तीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र चालू हैं।

डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों में कार्यान्वित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके निष्पादन के लिए इन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई पहलों को संयुक्त रूप से विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (23.02.2026 तक) के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के लिए सामान्य घटक के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत एमईआईटीवाई को आवंटित धन का विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
सामान्य घटक	2587.82	5429.80	4534.96	3737.81	3547.05	4371.76
अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)	253.00	530.20	487.70	382.78	346.36	427.55
अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)	204.00	428.00	377.84	307.42	279.59	345.14

****